RNI No. MPHIN/2015/64451 डाक पंजीयन क्र. MP/IDC/1525/2019-2021 IPT डाक द्वारा प्रेषण प्रति शुक्रवार indianplasttimes@gmail.com
www.Indianplasttimes.in

इंडियन प्लास्ट टाइम्स

■ INDORE ■ 11 DECEMBER TO 17 DECEMBER 2019 ■ प्रति बुधवार ■ वर्ष 05 ■ अंक 16 ■ पृष्ठ 8 ■ कीमत 5 रु.

Inside News

इंदौर में एसएमबी द्वारा पुराने कंप्यूटर के उपयोग से प्रोडक्टिविटी में 112 घंटों का नुकसान हो सकता है
Page 3

Income Tax में बड़ी राहत मिलने की संभावना
Page 4

नई जीएसटी रिटर्न प्रणाली को लेकर लोगों की राय जानने के लिये पहल
Page 7

editoria!

सरकार पर दारोमदार

रिजर्व बैंक ने साल की आखिरी द्विमासिक मौद्रिक नीति में ब्याज दरें घटाने से तो मना कर ही दिया, इस वित्त वर्ष में जीडीपी ग्रोथ का अनुमान भी 6.1 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी पर ला दिया। इससे पहले रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति ने लगातार पांच बार रीपो रेट में कटौती की थी। रीपो रेट वह दर है जिस पर आरबीआई बैंकों को कर्ज देता है। जीडीपी ग्रोथ के ताजा आंकड़े बता रहे थे कि जुलाई-सितंबर तिमाही में यह 4.5 फीसदी पर खिसक आई है, जो पिछले छह साल का सबसे निचला स्तर है। इसलिए उम्मीद जताई जा रही थी कि रिजर्व बैंक रीपो रेट में थोड़ी और कमी लाकर आर्थिक गतिविधियां तेज करने में सरकार का हाथ बंटा सकता है। लेकिन एक तो पिछली पांच कटौतियां आर्थिक विकास के मोर्चे पर कुछ खास फायदा नहीं दे सकीं, दूसरे, लगातार कटौतियों के बाद अब रिजर्व बैंक के पास पीछे जाने की गुंजाइश भी नहीं रह गई थी। खुदरा महंगाई दर का अनुमान उसने 4.7 से 5.1 प्रतिशत के बीच रखा है। ऐसे में रीपो रेट को मौजूदा 5.15 प्रतिशत से नीचे लाना नकारात्मक ब्याज दरों के खतरनाक दायरे में प्रवेश करने जैसा था। हालांकि आगे महंगाई नीचे जाने की स्थिति में आरबीआई ने अपने विकल्प खुले रखे हैं। केंद्रीय बैंक ने उम्मीद जताई है कि सरकार द्वारा पहले ही उठाए जा चुके कुछ कदमों के चलते अगली तिमाही में बेहतर नतीजे देखे जा सकते हैं, लेकिन उसके वक्तव्य में आए ब्यौरे अर्थव्यवस्था की नाजुक स्थिति की ओर ही इशारा करते हैं। ग्रोथ रेट बेशक, इससे पहले भी पांच फीसदी से नीचे गई है। इस लिहाज से मौजूदा स्थितियों को अभूतपूर्व नहीं कहा जा सकता। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि भारतीय अर्थव्यवस्था आज कुछ उसी तरह की चुनौतियों का सामना कर रही है जो 21वीं सदी के इन दो दशकों में सबसे कठिन मानी जाती रही हैं। 2008-09 जैसी वैश्विक मंदी आज नहीं है और 2012-13 जैसी पॉलिसी पैरालिसिस वाली स्थिति भी नहीं है। लेकिन पिछले दोनों मौकों पर सरकारें संकट से निपटने के लिए हाथ-पांव मारती नजर आती थीं, जबकि इस बार सरकार की कोशिश संकट जैसी धारणा को ही सिरे से खारिज करने की रही है। मौद्रिक नीति समिति की बैठक के बाद जारी रिजर्व बैंक के इस बयान के बाद सारी जय-क्षय सरकार पर ही आ गई है। ग्रोथ के चार प्रमुख कारकों में से तीन में फिलहाल कोई हलचल नहीं है। न विदेशी निवेश की कोई लहर करीब है, न निजी निवेश में कोई उत्साह देखा जा रहा है, न ही उपभोक्ता खर्च में किसी बड़ी बढ़त के आसार हैं। ऐसे में सारी उम्मीदें सरकारी निवेश पर ही टिकी हैं। यह सरकार के कौशल का इम्तहान है। मंत्रियों की कोशिश छोटे-छोटे मामलों में भी आर्थिक सक्रियता की गुंजाइश बनाने की होनी चाहिए, बयान बहादुरी का वक्त जा चुका है। रिजर्व बैंक ने सुझाया है कि लंबित परियोजनाओं के रास्ते की अड़चनें दूर करके इन्हें जल्द से जल्द चालू करना अभी के लिए सबसे बड़ा लक्ष्य होना चाहिए।

इंदौर में उद्योगों का तकनीकी महाकुंभ

इंडस्ट्रीयल इंजीनियरिंग एक्सपों 2019 20 से 23 तक

इंदौर। मध्यप्रदेश समीट आयोजन एवं मध्यप्रदेश शासन के प्रयासों को आगे बढाते हुए उद्यमियों को इंजीनियरिंग क्षेत्र में एक प्लेटफार्म प्रदान करने के लिए इंडियन प्लास्टपेक फोरम और एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्रीज मध्यप्रदेश के सहयोग से फ्युचर कम्युनिकेशन्स द्वारा 20 से 23 दिसंबर 2019 तक इंडस्ट्रीयल इंजीनियरिंग एक्सपों 2019 का आयोजन लाभगंगा एग्झीबिशन सेन्टर, इंदौर में होने जा रहा है। एक्सपों 2019 में सम्पूर्ण भारत से लघु एवं मध्यम उद्योगों से जुडे लगभग 300 मैन्यूफैक्चरिंग इकाईयां, सप्लायर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, ट्रेडर्स सहभागिता कर रहे है। इंडियन प्लास्टपेक फोरम के अध्यक्ष श्री सचिन बंसल ने बताया कि प्रदर्शनी में इंदौर में बनने वाले उत्पादों की जानकारी मिलती है, इंदौर के अलावा आसपास के क्षेत्रों के उद्योग भी इसमें सम्मिलित होकर प्रदर्शित उत्पादों की जानकारी लेकर अपने व्यवसाय में इसका उपयोग कर सकते है। इस वर्ष प्रदर्शनी में स्वच्छता कार्यक्रम भी रखा गया है इसके साथ ही इसमें 4 प्रकार की लाईटवेट डस्टबीन भी लांच करेगें।

एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्रीज मध्यप्रदेश के अध्यक्ष श्री प्रमोद डफरिया ने बताया कि इंदौर एवं मध्यप्रदेश उद्योग संभावित क्षेत्र होने से व्यवसाय का उपयुक्त वातावरण यहा है जहां विविध प्रकार के छोटे, मध्यम एवं वृहद उद्योग लाभ उठा सकते है। फ्युचर कम्युनिकेशन के श्री अमेय गोखले ने जानकारी देते बताया कि आयोजन में इंजीनियरिंग एवं मैन्युफैक्चरिंग, ऑटो कम्पोनेंट, ऑटोमेशन एंड रोबोटिक आदि उत्पादों एवं मशीनरी का प्रदर्शन किया जा रहा है इसमें देशी एवं विदेशी कंपनियों द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। एक्सपों में लगभग 300 स्टॉल्स रहेगें जहां जनरल इंजीनियरिंग, कॉस्टींग एवं फोर्जीग, अलाइड केटेगरी में प्रिंटर्स पैकेजिंग मटेरियल्स, लैब इक्वीपमेंट्स, हेल्थकेयर प्रॉडक्ट, केमिकल प्रोसेस मशीनरी, इलेक्ट्रानिक्स एंड इलेक्टीकल, मशीन टूल्स, स्पेशल परपज मशीन, वायर्स एंड केबल्स आदि जैसे उत्पादों व मशीनरी के लिए लाभकारी प्लेटफार्म होगा।

एग्झीबिशन को विजिटर्स के लिए निशुल्क रखा गया है ताकि अधिक से अधिक उद्योगपतिगण, इस क्षेत्र से जुडे व्यक्ति इसका अवलोकन कर सकें तथा नये इनोवेशन्स, नई तकनीकी जानकारी के साथ अपने उद्योगों में इनको क्रियान्वित कर लाभ ले सके। अंत में एसोसिएशन के मानद सचिव श्री सुनील व्यास ने प्रेस एवं मिडिया के सहयोग की अपेक्षा व्यक्त करते हुए उपस्थितों के प्रति आभार माना। इस अवसर पर श्री योगेश मेहता, श्री दिलीप देव, श्री हरीश नागर, श्री तरूण व्यास, श्री अनील पालीवाल, श्री हेमेन्द्र बोकाडिया, श्री सतीश मित्तल, श्रीमती रीना जैन, श्री राजकुमार मौर्या, श्री रमेश पटेल, श्री लक्ष्मण, आदि अन्य उपस्थित थे।

दुनिया की सबसे अहम तेल कंपनी अरामको ने की रियाद शेयर बाजार में कारोबार की शुरुआत

एजेंसी

सऊदी अरब की सरकारी तेल कंपनी अरामको दुनिया की सबसे अहम तेल कंपनियों में से एक है और कच्चे तेल की सबसे बड़ी निर्यातक है। आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) से अरामको ने रिकॉर्ड 25.6 अरब डॉलर जुटाए थे। बुधवार को स्थानीय शेयर बाजार में इसका कारोबार शुरू हुआ। अरामको द्वारा आईपीओ की दर 32 रियाल यानी 8.53 डॉलर प्रति शेयर तय की गई थी। जबकि प्री ओपन के दौरान कंपनी का शेयर इससे 10 फीसदी ऊपर 35.2 रियाल यानी 9.39 डॉलर प्रति शेयर पर था। अरामको का बाजार पूंजीकरण बढ़ कर 1.88 लाख करोड़ डॉलर हो गया है।

तेल पर निर्भरता कम करना चाहता है सऊदी अरब

दरअसल सऊदी अरब अर्थव्यवस्था की तेल पर निर्भरता को कम करना चाहता है। आईपीओ लाने के पीछे सऊदी राजघराने के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की सुधारों को बढ़ाने की सोची समझी रणनीति है। साल 2016 में पहली बार मोहम्मद बिन सलमान ने आईपीओ बनाए जाने के बारे में घोषणा की थी।

सऊदी अरामको ने अलीबाबा को पछाड़ा

कंपनी का मूल्यांकन 1,700 अरब डॉलर बैठता है। इसके साथ ही आईपीओ से पैसे जुटाने के मामले में सऊदी अरामको दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बन गई है। अरामको के बाद चीन की अलीबाबा ने आईपीओ से सबसे ज्यादा पैसे जुटाए हैं। साल 2014 में अलीबाबा ने 25 अरब डॉलर जुटाए थे।

2018 में कमाया था 111 अरब डॉलर का लाभ

साल 2018 में कंपनी ने 111 अरब डॉलर का लाभ कमाया था। ये एपल और गूगल की कंपनी एल्फाबेट के कुल सालाना लाभ से भी अधिक है। बता दें कि अक्तूबर माह में अरामको के आईपीओ में थोड़ा विलंब हुआ था। हाल ही में सऊदी अरामको के क्रूड ऑयल फैसिलिटी सेंटर्स पर ड्रोन हमला हुआ था। जिसकी वजह से 28 साल बाद कच्चे तेल में एक दिन की सबसे ज्यादा तेजी आई थी।

विदेशी बाजारों में ऊंची कीमतों के बावजूद वायदा कारोबार में कच्चा तेल गिरा

नयी दिल्ली। एजेंसी

वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों तेजी के बावजूद प्रतिभागियों के सौदे घटाने से वायदा कारोबार में बुधवार को कच्चा तेल 19 रुपये गिरकर 4,176 रुपये प्रति बैरल पर आ गया। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में, दिसंबर महीने में डिलिवरी वाला कच्चा तेल 19 रुपये यानी 0.45 प्रतिशत गिरकर 4,176 रुपये प्रति बैरल पर रहा। इसमें 26,436 लॉट का कारोबार हुआ। इसी प्रकार, जनवरी महीने में डिलिवरी वाला कच्चा तेल 13 रुपये यानी 0.32 प्रतिशत लुढ़क कर 4,106 रुपये प्रति बैरल पर आ गया। इसमें 863 लॉट का कारोबार हुआ। वैश्विक स्तर, न्यूयॉर्क में वेस्ट टेक्सॉस इंटरमीडिएट कच्चा तेल 0.59 प्रतिशत बढ़कर 58.89 डॉलर प्रति बैरल जबकि ब्रेंट कच्चा तेल 0.73 प्रतिशत चढ़कर 63.87 डॉलर प्रति बैरल पर रहा।

राजस्व कमी को दूर करने के लिये कई वस्तुओं पर बढ़ सकती है जीएसटी दरें

नयी दिल्ली। एजेंसी

माल एवं सेवाकर (जीएसटी) की अगले सप्ताह होने वाली बैठक में जीएसटी की दर और स्लैब में बड़ा बदलाव हो सकता है। जीएसटी की अब तक की राजस्व वसूली संतोषजनक नहीं रही है। इसकी वजह से केन्द्र तथा राज्यों की राजस्व वसूली काफी दबाव में आ गई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता की अध्यक्षता वाली जीएसटी परिषद की अगले सप्ताह 18 दिसंबर को बैठक होने वाली है। जीएसटी के सभी फैसले जीएसटी परिषद में ही लिये जाते हैं। यह बैठक ऐसे समय हो रही है जबकि जीएसटी संग्रह उम्मीद से कम रहा है और कई राज्यों का मुआवजा भी लंबित है। राज्य उन्हें जल्द से जल्द इसकी भरपाई किये जाने की मांग कर रहे हैं। जीएसटी के तहत इस समय मुख्यतः चार दरें -- पांच प्रतिशत, 12 प्रतिशत, 18 और 28 प्रतिशत हैं। इसके अलावा 28 प्रतिशत की श्रेणी में आने वाली माल एवं सेवाओं पर उपकर भी लिया जाता है। यह उपकर एक से लेकर 25 प्रतिशत के दायरे में लगाया जाता है। केन्द्र और राज्यों के अधिकारियों के एक समूह ने मंगलवार को बैठक कर जीएसटी दरों को तर्कसंगत बनाने की अपनी सिफारिशों को अंतिम रुप दिया। इसमें कई विकल्पों पर विचार किया गया जिनमें से एक यह है कि पांच प्रतिशत की दर को बढ़ाकर 8 प्रतिशत और 12 प्रतिशत की दर को बढ़ाकर 15 प्रतिशत कर दिया जाये। जीएसटी दरों को तर्कसंगत बनाये जाने के मामले में विस्तृत प्रस्तुतीकरण जीएसटी परिषद की बैठक के दौरान ही दिया जायेगा। इसके साथ ही अन्य मुद्दों के अलावा राज्यों की बढ़ती मुआवजा जरूरतों को देखते हुये परिषद की बैठक में कुछ और उत्पादों पर उपकर वसूले जाने पर भी विचार विमर्श किया जा सकता है।

जानकार सूत्रों ने बताया कि परिषद की बैठक में जीएसटी दरों को आपस में विलय कर उनकी संख्या मौजूदा चार स्लैब से घटाकर तीन भी की जा सकती है। परिषद विभिन्न छूटों पर भी फिर से गौर कर सकती है और यह भी देखेगी कि क्या कुछ सेवाओं पर उपकर लगाया जा सकता है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार अप्रैल से नवंबर की अवधि में केन्द्रीय जीएसटी प्राप्ति 2019- 20 के बजट अनुमान से 40 प्रतिशत कम रही है। इस अवधि में वास्तविक सीजीएसटी संग्रह 3,28,365 करोड़ रुपये रहा है जबकि बजट अनुमान 5,26,000 करोड़ रुपये रखा गया है। पिछले वित्त वर्ष 2018-19 में वास्तविक केन्द्रीय जीएसटी प्राप्ति 4,57,534 करोड़ रुपये रहा जबकि वर्ष के लिये अस्थाई अनुमान 6,03,900 करोड़ रुपये का लगाया गया था।

इससे पहले 2017- 18 में सीजीएसटी संग्रह 2,03,261 करोड़ रुपये रहा था। इस बीच देश की जीडीपी वृद्धि चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में पिछली 26 तिमाहियों में सबसे कम 4.5 प्रतिशत रह गई। विनिर्माण क्षेत्र में सकल मूल्य वर्धन पिछली नौ तिमाहियों में सबसे कम रहने की वजह से यह गिरावट आई। इससे पहले 2012- 13 की चौथी तिमाही में जीडीपी वृद्धि दर 4.3 प्रतिशत रही थी। बहरहाल, जीएसटी की प्रस्तावित बैठक काफी अहम हो सकती है। पिछले कुछ महीनों के दौरान जीएसटी और उपकर की वसूली काफी कम रही है। जीएसटी परिषद की ओर से सभी राज्यों के राज्य जीएसटी आयुक्तों को भेजे गये पत्र में इस बात का उल्लेख किया गया है।

भारतीय कंपनियों से भेदभाव करने वाले देशों के साथ 'जैसे को तैसा' वाला व्यवहार होगाः गोयल

नयी दिल्ली।एजेंसी

केंद्रीय उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारतीय कंपनियों के साथ अनुबंध के मामले में भेदभाव करने वाले किसी भी देश को सार्वजनिक खरीद ठेकों में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी । गोयल ने आयात - निर्यात (एक्जिम) बैंक की ओर से आयोजित एक कार्यक्रम में कहा कि ' मुक्त एवं समान पहुंच ' की नीति इस सरकार ने दो साल पहले अपनाई है । उन्होंने कहा, 'जब हमने क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी (आरसीईपी) का हिस्सा नहीं बनने का फैसला किया तो उसका एक मुख्य कारण यह भी था कि दूसरे देशों में हमारी कंपनियों को उन क्षेत्रों में बराबर और उचित अवसर नहीं मिलते हैं , जिनमें वे मजबूत स्थिति में हैं। ' केंद्रीय मंत्री ने कहा कि उन्होंने कभी नहीं सुना कि चीन अपने सरकारी ठेकों को किसी और के लिए खोला हो । उन्होंने कहा , कई आसियान देश यहां तक कि जापान और कोरिया भी इस तरह की शर्तें रखते हैं कि कई भारतीय कंपनियों को निविदाओं में भाग लेने की अनुमति नहीं मिले।' गोयल ने कहा , आज हमारी नीति यह है कि यदि हमारी कंपनियों को किसी दूसरे देश में अवसर या कारोबार करने की अनुमति नहीं मिलती है तो मैं आश्वासन दे सकता हूं कि हम उन्हें यहां भाग लेने की अनुमति नहीं देंगे। '

डिजिटल रेस में अमेरिका और चीन को पछाड़ सकता है भारतः रिपोर्ट

नई दिल्ली। एजेंसी

साल 2030 तक भारत एक नया मुकाम हासिल कर सकता है। डिजिटल की रेस में भारत अमेरिका और चीन जैसे देशों से आगे निकल सकता है। आगामी वर्ष में अमेरिका की अमेजन और चीन की टेंसेंट जैसी भारत में आठ कंपनियां हो सकती हैं। अमेरिका की जीवीजी कैपिटल ने एक 'कौन जीतेगा अगली डिजिटल रेस' नाम से एक रिपोर्ट जारी की, जिसमें यह अनुमान लगाया गया है।

इन क्षेत्रों में आगे बढ़ सकता है भारत

रिपोर्ट के अनुसार, भारत में हेल्थ, फूड, रिटेल, फाइनेंशल सर्विस, कंज्यूमर प्रोडक्ट, रियल एस्टेट, लॉजिस्टिक और टेलीकॉम जैसे बड़े क्षेत्रों में तेजी से विकास हो सकता है। भारत की एयरटेल, डीमार्ट, गोदरेज और रिलायंस जैसी अन्य कंपनियां काफी मजबूत हैं।

पहली डिजिटल रेस में आई ये कंपनियां

रिपोर्ट में कहा गया है कि पहली डिजिटल रेस यानी साल 1995 से अबतक दुनिया में आठ डिजिटल दिग्गज कंपनियां आई हैं, जिनमें से छह कंपनियां अमेरिका की हैं। इनमें अमेजन, एपल, फेसबुक, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और नेटफ्लिक्स शामिल हैं। वहीं अलीबाबा और टेंसेंट चीन की कंपनियां हैं। साथ ही दुनिया की 10 सबसे ज्यादा वैल्यूएबल कंपनियों में से सात कंपनियां इन्हीं में से हैं।

2020 - 2030 में हो सकती हैं 40 बड़ी कंपनियां

वहीं दूसरी डिजिटल रेस यानी 2020 से 2030 में भारत जैसे 15 देशों से लगभग 40 नए डिजिटल दिग्गज पैदा होने की संभावना है। उभरती बड़ी कंपनियों के पास बढ़ोतरी का ज्यादा मौका है।

5000 कंपनियों की स्टडी पर आधारित है रिपोर्ट

बता दें कि अमेरिका की जीवीजी कैपिटल द्वारा जारी की गई 'कौन जीतेगा अगली डिजिटल रेस' रिपोर्ट 100 देशों की 5000 कंपनियों की स्टडी के आधार पर तैयार की गई है।

दिवालिया कंपनियों के नए मालिक को पिछले के किए की सजा नहीं मिलेगी!

मुंबई। एजेंसी

दिवालिया कंपनियों के नए मालिकों को पिछले मालिकों के अपराध की सजा से बचाने के लिए सरकार दिवाला कानून (इनसॉल्वेंसी कोड) में बदलाव करने जा रही है। इस मामले से वाकिफ कम से कम तीन सूत्रों ने यह जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि कैबिनेट जल्द ही इसके लिए तीन साल पुराने इनसॉल्वेंसी ऐंड बैंकरप्सी कोड में बदलाव को मंजूरी दे सकती है। एक सूत्र ने बताया, 'सरकार जल्द ही दिवाला कानून में बदलाव की कैबिनेट से मंजूरी लेगी ताकि नैशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल (ञ्थ्ऊ) के जरिये खरीदी गई कंपनियों को सुरक्षा मिल सके।' उन्होंने बताया, 'इससे ऐसी संपत्तियों को खरीदने वालों का भरोसा बढ़ेगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो इन एसेट्स को खरीदने वालों के कानून की गिरफ्त में फंसने का डर बना रहेगा।'

देश की ग्रोथ में गिरावट टेंपरेरी, तेजी की संभावना बरकरारः CEA

मुख्य आर्थिक सलाहकार के मुताबिक देश की आर्थिक सुस्ती चक्रीय है, लेकिन आगे इसमें रिकवरी की संभावना बनी हुई

नई दिल्ली। एजेंसी

भारत चक्रीय (साइक्लिकल) यानी अस्थायी आर्थिक सुस्ती का सामना कर रहा है। देश की तेज ग्रोथ की संभावना अभी बनी हुई है यानी इकनॉमिक रिकवरी होगी। देश के मुख्य आर्थिक सलाहकार के सुब्रमण्यन ने यह बात कही है। उन्होंने कहा कि देश में आर्थिक सुस्ती है। इसमें कोई शक नहीं। बस, यह समझने की जरूरत है कि यह ढांचागत (स्ट्रक्चरल) यानी लंबे समय की सुस्ती है या यह चक्रीय है। भारत की जीडीपी ग्रोथ वित्त वर्ष 2020 की पहली तिमाही में 5 प्रतिशत के साथ गिरकर 6 साल के निचले स्तर पर आ गई थी। यह दूसरी तिमाही में 4.5 प्रतिशत तक फिसल गई। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने भी वित्त वर्ष 2020 में भारत की जीडीपी ग्रोथ का अनुमान 6.1 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया है। फिक्की यंग लीडर्स को संबोधित करते हुए सोमवार को सुब्रमण्यन ने कहा, 'मुझे लगता है कि सुस्ती काफी हद तक चक्रीय है क्योंकि देश की डेमोग्राफी में कोई बदलाव नहीं हुआ है। मीडियम टर्म में मांग भी अप्रभावित दिख रही है। कंपनियों की आपूर्ति क्षमता भी बेअसर है।' उन्होंने कहा, 'हम कई रिफॉर्म्स यानी सुधार कर रहे हैं और इनसे अर्थव्यवस्था में उत्पादकता (प्रॉडक्टिविटी) बढ़ती है।' मुख्य आर्थिक सलाहकार ने बताया कि देश की पोटेंशियल ग्रोथ रेट जस की तस बनी हुई है। इसलिए इकनॉमिक रिकवरी में मुझे कोई शक नहीं है। हालांकि, उन्होंने यह नहीं बताया कि वह कब तक रिकवरी की उम्मीद कर रहे हैं। सुब्रमण्यन ने कहा, 'जैसा कि हमने आर्थिक सर्वेक्षण में दिखाया था कि भारत जैसी इकनॉमी में निवेश, खासतौर पर निजी क्षेत्र के निवेश से ग्रोथ बढ़ती है।' उन्होंने कहा कि सरकार बहुत सोच-समझकर आर्थिक सुधार कर रही है। मुख्य आर्थिक सलाहकार ने बताया, 'हमने जो कदम उठा रहे हैं, चाहे वह कंपनियों के टैक्स में कटौती हो या सैलरी कोड और इंडस्ट्रियल रिलेशंस, हम निवेश के लिए परिस्थितियों को बेहतर बना रहे हैं। टिकाऊ ग्रोथ के लिए हमें इन्हीं चीजों की जरूरत है।' उन्होंने बताया, 'अर्थशास्त्र के नियम मजबूत हैं। जिस चीज से ग्रोथ कम हुई है, वही इसे ऊपर ले जाएगी।' वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पिछले महीने कहा था कि देश की ग्रोथ बेशक कम हुई है, लेकिन यहां मंदी आने का जोखिम नहीं है। उन्होंने इससे पहले सितंबर में कॉरपोरेट टैक्स को 35 प्रतिशत (सरचार्ज और उपकर सहित) से घटाकर 25.17 प्रतिशत कर दिया था। वित्त मंत्री ने इसके साथ नई मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों के लिए टैक्स को 25 प्रतिशत से कम करके 15 प्रतिशत कर दिया था। सुब्रमण्यन ने यह भी कहा कि सरकार हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठी है। उसे जो करना चाहिए, वह कर रही है। हम संबंधित पक्षों के साथ लगातार बात कर रहे हैं और इसका पता लगा रहे हैं कि कौन से उपाय रिकवरी के लिए किए जा सकते हैं।

इंदौर में एसएमबी द्वारा पुराने कंप्यूटर के उपयोग से प्रोडक्टिविटी में 112 घंटों का नुकसान हो सकता है- माईक्रोसॉफ्ट का अध्ययन

इंदौर में पुराने कंप्यूटर एवं ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल कर रही एसएमबी की सुरक्षा में सेंध लगाई गई।

एसएमबी को कार्यशील खर्चों में कटौती एवं व्यवसायिक वृद्धि बढ़ाने के लिए विंडोज़ 10 कंप्यूटर का उपयोग करना हुआ जरूरी।

इंदौर। आईपीटी नेटवर्क

इंदौर में चार साल से ज्यादा पुराने कंप्यूटर एवं पुराने ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल करने वाले स्मॉल एवं मीडियम बिज़नेस (एसएमबी) को नए कंप्यूटर के मुकाबले कार्यस्थल की उत्पादकता में 3 गुना से ज्यादा नुकसान हो सकता है। पुराने कंप्यूटर के इस्तेमाल से न केवल कार्यक्षमता घटती है, बल्कि संस्थानों को सुरक्षा खामियों एवं आईटी में सेंध का जोखिम भी रहता है। डेटा को रिकवर करना एवं व्यवसाय की निरंतरता बनाए रखना इंदौर की एसएमबी के लिए सबसे बड़ी चुनौतियों में है। अकेले पिछले साल, इंदौर में सर्वे में शामिल 21 प्रतिषत एसएमबी ने कहा कि उनकी सुरक्षा में सेंध लगाई गई।

इंदौर की आधी (50 प्रतिशत) एसएमबी पुराने हो चुके कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहे हैं और उनमें से 77 फीसदी विंडोज़ के पुराने वर्जन पर चल रहे हैं। ये परिणाम ग्लोबल एसएमबी आईटी मार्केट रिसर्च एवं एनालिस्ट संगठन, टेकएज़ल के साथ गठबंधन में किए गए माईक्रोसॉफ्ट के लेटेस्ट अध्ययन में सामने आए, जिसमें एषिया पैसिफिक में लगभग 2000 एसएमबी के विचार लिए गए। कार्यस्थल की आधुनिक कार्ययोजना को अपना चुके इंदौर के एसएमबी को व्यवसाय व कर्मचारियों के मामले में अनेक फायदे हुए, जिनमें उच्च उत्पादकता, बेहतर सुरक्षा एवं कम कार्यशील लागत हैं।

इंदौर की 65 प्रतिषत एसएमबी ने नए कंप्यूटर अपनाकर आईटी एफिषियंसी में सुधार किया।

उनमें से आधे इस बात पर सहमत थे कि नए कंप्यूटर अपनाने से क्लाउड एवं मोबिलिटी समाधानों द्वारा उपयोग का बेहतर अनुभव सुनिष्चित हुआ एवं उनमें से 85 फीसदी के रखरखाव के खर्च में कमी आई।

इंदौर की 90 फीसदी एसएमबी ने कहा कि नए कंप्यूटर ने उन्हें विस्तृत सुरक्षा एवं डेटा प्रोटेक्षन प्राप्त करने में मदद की और उनमें से तीन चौथाई (75 प्रतिषत) को कर्मचारियों की ज्यादा उत्पादकता का लाभ मिला।

माईक्रोसॉफ्ट इंडिया की ग्रुप डायरेक्टर-डिवाईसेस सुश्री फरहाना हक, ने कहा, ''टेक्नॉलॉजी बड़े एवं छोटे व्यवसायों को समर्थ बनाती है और एसएमबी को आईटी निवेष द्वारा अपनी वर्तमान एवं भविष्य की प्रगति को होने वाले फायदों को समझना चाहिए। एसएमबी में देष के 110 मिलियन लोग काम करते हैं तथा ये भारत की आर्थिक वृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। माईक्रोसॉफ्ट भारत में एसएमबी के साथ मिलकर काम करना चाहता है ताकि यह उन्हें अपने उद्देष्य प्राप्त करने एवं प्रतिस्पर्धी बाजार में सफल होने में मदद कर सके।''

उपयोग का अंतर कम होता हुआ

अध्ययन के अनुसार, एसएमबी द्वारा विविध व्यवसायिक कार्यों में नई टेक्नॉलॉजी का इन्फ्रास्ट्रक्चर अपनाए जाने में होने वाला निरंतर विलंब विविध कारणों से था, जिनमें ऐप की इनकॉम्पेटिबिलिटी एवं नए कंप्यूटर में आवष्यक क्षमताओं के बारे में जानकारी की कमी शामिल है। इंदौर में सर्वे में शामिल 83 फीसदी एसएमबी ने कहा कि उनके यहां कंप्यूटर का नवीनीकरण करने की नीति नहीं तथा वो इसका पालन नहीं करते। हालांकि वास्तविकता यह है कि कंप्यूटर की सामरिक नवीनीकरण नीति की कमी के कारण आगे चलकर बड़ा नुकसान हो सकता है। इंदौर की एसएमबी का अनुभव रहा है कि पुराने कंप्यूटर की मरम्मत नए कंप्यूटर के मुकाबले पाँच गुना ज्यादा होती है। इस वजह से कम से कम 112 घंटों के प्रोडक्टिव समय का नुकसान होता है।

अपने व्यवसायिक उद्देष्य पूरे करने के लिए एसएमबी अपने पुराने कंप्यूटर का नवीनीकरण कर सकती हैं क्योंकि इससे उन्हें सर्वश्रेष्ठ उपयोग के लिए सिक्योरिटी पैच एवं नियमित तौर पर ऑपरेटिंग सिस्टम के अपडेट्स मिलते हैं। ऐप की कॉम्पेटिबिलिटी की समस्याओं को विंडोज़ 10 में दूर कर दिया गया है। यह विंडोज़ का अब तक का सबसे ज्यादा ऐप कॉम्पेटिबल वर्जन है, जिसकी सर्वश्रेष्ठ प्रैक्टिसेस में डायग्नोस्टिक डेटा एवं ट्रबलषूटिंग के लिए के लिए ऐप टेलीमीट्री, आईएसवी पार्टनरषिप्स तथा लूपिंग फीडबैक साइकल्स शामिल हैं। विंडोज़ 7 की सपोर्ट बंद होने के साथ एसएमबी को नए कंप्यूटर एवं ऑपरेटिंग सिस्टम्स की ओर बढ़ना होगा क्योंकि यूज़र्स को विंडोज़ 7 पर चलने वाले कंप्यूटर के लिए सपोर्ट या सिक्योरिटी अपडेट्स नहीं मिलेंगे। इसमें नए सिक्योरिटी अपडेट्स, नॉन सिक्योरिटी हॉटफिक्स, फ्री या पेड असिस्टेड सपोर्ट विकल्प एवं ऑनलाईन टेक्निकल कंटेंट अपडेट्स शामिल हैं।

ADB ने भारत के GDP ग्रोथ का अनुमान 6.5% से घटाकर 5.1% किया

नई दिल्ली। एजेंसी

एशियन डेवलपमेंट बैंक ने 2019-20 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान 6.5 प्रतिशत से घटाकर 5.1 प्रतिशत कर दिया। एडीबी ने सितंबर में भारत की आर्थिक वृद्धि दर 2019-20 के लिए 6.5 प्रतिशत और उसके बाद 7.2 प्रतिशत रहने का अनुमान व्यक्त किया था।

ग्रोथ रेट घटने की वजह

ADB ने कहा कि खराब फसल से ग्रामीण क्षेत्र की बदहाल स्थिति तथा रोजगार की धीमी वृद्धि दर ने उपभोग को प्रभावित किया है। इसके कारण वृद्धि दर के अनुमान को घटाया गया है। उसने कहा कि अनुकूल नीतियों के कारण आर्थिक वृद्धि दर अगले वित्त वर्ष में मजबूत होकर 6.5 प्रतिशत पर पहुंच जाने का अनुमान है।

RBI ने भी घटाया GDP ग्रोथ का अनुमान

बता दें कि इससे पहले, भारतीय रिजर्व बैंक ने भी अपनी मौद्रिक नीति समीक्षा में वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान देश की GDP बढ़त के अनुमान को 6.1 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी कर दिया है। इसके पहले रिजर्व बैंक ने अक्टूबर महीने में नीतिगत समीक्षा में यह अनुमान जाहिर किया था कि वित्त वर्ष 2019-20 में जीडीपी बढ़त 6.1 फीसदी हो सकती है, लेकिन अब रिजर्व बैंक ने कहा है कि जोखिम पर संतुलन बनने के बावजूद जीडीपी ग्रोथ अनुमान से कम रह सकती है। इस वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में जीडीपी ग्रोथ 6 साल के निचले स्तर 4.5 फीसदी तक पहुंच गई थी।

GDP दर 6 साल में सबसे कम

चालू वित्त वर्ष के दूसरी तिमाही यानी जुलाई-सितंबर माह के लिए सकल घरलू उत्पाद घटकर 4.5 फीसदी के स्तर पर आ गया है। इसके पहले की तिमाही में यह जीडीपी दर 5 फीसदी के स्तर पर था. यह पिछली 26 तिमाही में सबसे कम है। पहली तिमाही में विकास दर 5 फीसदी पर आ गई है. वहीं, पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में जीडीपी ग्रोथ रेट 7 फीसदी दर्ज की गई थी।

भारत की 'नाविक' उपग्रह नौवहन प्रणाली के साथ डेटा का आदान-प्रदान करेगा अमेरिका

वाशिंगटन। एजेंसी

अमेरिकी संसद ने भारत के 'नाविक' उपग्रह को ''सहयोगी'' नौवहन उपग्रह प्रणाली के तौर पर मान्यता देने को सहमति दे दी है जिससे अमेरिकी उपग्रह नौवहन प्रणाली इस उपग्रह के साथ सहयोग करेगी या डेटा का आदान-प्रदान करेगी। अमेरिका ने यूरोपीय संघ की गैलिलियो और जापान के क्यूजेडएसएस को भी ''सहयोगी'' नौवहन उपग्रह प्रणाली के तौर पर मान्यता दे रखी है। राष्ट्रीय रक्षा प्राधिकरण कानून (एनडीएए), 2020 की कांफ्रेंस रिपोर्ट के तौर पर उसने रूस की जीएलओएनएएसएस और चीन की बिदोउ को ''गैर सहयोगी प्रणाली'' घोषित किया है। इसका मतलब है कि अमेरिकी उपग्रह नौवहन प्रणाली इन दो उपग्रह नौवहन प्रणालियों के साथ सहयोगी नहीं करेगी या डेटा का आदान-प्रदान नहीं करेगी। स्वदेश निर्मित 'नाविक' एक स्वायत्त क्षेत्रीय उपग्रह नौवहन प्रणाली है जो सटीक रियल टाइम पॉजिशनिंग तथा टाइमिंग सेवाएं मुहैया कराती है।

Income Tax में बड़ी राहत मिलने की संभावना

टैक्स रेट में हो सकते हैं ये बदलाव

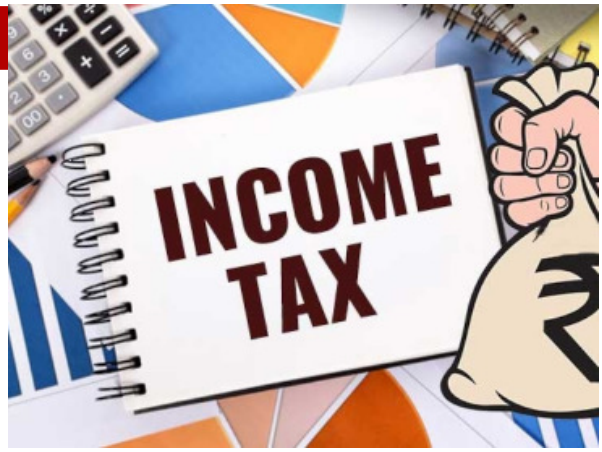

नई दिल्ली। आईपीटी नेटवर्क

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाल ही में Income Tax में कटौती का संकेत दिया है। विश्लेषकों के मुताबिक सरकार वित्त वर्ष 2020-21 के बजट में आयकर के मोर्चे पर राहत का ऐलान कर सकती है। इससे देश के करोड़ों वेतनभोगियों को सीधा फायदा होगा, जो आर्थिक सुस्ती के इस दौर में सरकार की ओर से रिलीफ की उम्मीद कर रहे हैं, क्योंकि केंद्र सरकार ने इस साल सितंबर में कॉरपोरेट टैक्स में भारी कमी के जरिए देश के उद्योग जगत को बड़ी राहत दी थी।

सीतारमण ने बीते सप्ताह राष्ट्रीय राजधानी में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा था कि सरकार देश में खपत बढ़ाने के लिए झ्रैदर्हंत ध्म्दस ऊँ में कटौती समेत कई उपायों पर विचार कर रही है। हालांकि, आयकर में छूट को लेकर उन्होंने आगामी बजट तक इंतजार करने की बात कही। आगामी बजट अगले साल फरवरी में पेश किया जाएगा। ऐसे में आइए जानते हैं देश का मिडिल क्लास आयकर में कितनी छूट की उम्मीद कर सकता है।

संभव है Income Tax में बड़ी छूट का ऐलान

एँ्ड की पूर्व Chief Economist बृंदा जागीरदार ने कहा कि अर्थव्यवस्था को सुस्ती के दौर से निकालने के लिए खपत और निवेश दोनों बढ़ाने की जरूरत है। सरकार ने Corporate Tax cut के जरिए कंपनियों को राहत तो दे दी है लेकिन मिडिल क्लास का कॉन्फिडेंस वापस लाने के लिए Individual Income Tax में कमी की जानी चाहिए। जागीरदार ने कहा कि GST लागू होने के बाद सरकार Indirect Tax को लेकर बहुत कुछ नहीं कर सकती है लेकिन Direct Tax को लेकर कुछ गुंजाइश अब भी नजर आ रही है। उन्होंने कहा, ''सरकार मिडिल क्लास के हाथ में पैसे देने के लिए और खपत बढ़ाने के लिए आगामी बजट में Income Tax से जुड़ी बड़ी छूट का ऐलान कर सकती है। यह छूट इनकम टैक्स स्लैब और रेट दोनों में मिल सकती है।''

टैक्स रेट में कमी से बढ़ सकता है रेवेन्यू कलेक्शन

टैक्स एक्सपर्ट बलवंत जैन ने इस संबंध में 'Laffer Curve' सिद्धांत को उद्धत किया। यह सिद्धांत टैक्स रेट और सरकार के राजस्व के वसूली के संबंध को दिखाता है। उन्होंने कहा कि इनकम टैक्स में कमी करने से लोगों की क्रय शक्ति बढ़ेगी। इससे Indirect Tax के रूप में राजस्व बढ़ेगा ही।

उन्होंने पांच लाख रुपये से दस लाख रुपये की आय पर आयकर के रेट को 20 फीसद से घटाकर 10 फीसद करने की हिमायत की। इसके साथ ही 10-25 फीसद तक की सालाना आय पर 20 फीसद कर लगाने की वकालत की। वहीं, बकौल जैन 25 लाख रुपये से 1 करोड़ रुपये तक की आय पर 30झ का टैक्स लेने की बात कही। जैन के मुताबिक सरकार को एक करोड़ रुपये से अधिक की सालाना व्यक्तिगत आय पर 40 फीसद तक का टैक्स लेना चाहिए।

ओवरऑल पैकेज की है जरूरत

रेटिंग एजेंसी CRISIL के Chief Economist डी के जोशी के मुताबिक देश में डिमांड बढ़ाने और इकोनॉमी को Slowdown से बाहर निकालने के लिए सरकार को एक नहीं बल्कि कई कदम उठाने होंगे। उन्होंने कहा कि Income Tax में कटौती उनमें से एक उपाय हो सकता है। वित्त मंत्री सीतारमण ने भी कहा था कि सरकार आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए कर में कटौती सहित कई उपायों के बारे में सोच रही है।

जोशी ने एक सवाल के जवाब में कहा, ''इकोनॉमी को मजबूती देने के लिए एक ओवरऑल पैकेज की जरूरत है। इसके लिए लोगों की खर्च करने की शक्ति बढ़ाये जाने की जरूरत है। सरकार को सबसे कम आय वाले लोगों के हाथ में पैसे देने होंगे। यह राशि मनरेगा जैसी योजनाओं के जरिए दी जा सकती है। ध्म्दस ऊँ में कटौती भी एक उपाय हो सकता है और यह डिमांड बढ़ाने में कॉरपोरेट टैक्स में कटौती के फैसले से भी ज्यादा मददगार साबित होगा।''

Personal Income Tax में कटौती की ये बातें ऐसे समय में हो रही हैं जब देश की आर्थिक वृद्धि की रफ्तार चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में घटकर छह साल से भी अधिक समय के निचले स्तर पर पहुंच गई है। देश की उ्रझ वृद्धि दर जुलाई से सितंबर के बीच 4.5 फीसद रही। सरकार इस साल अब तक देश की अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए कई कदम उठा चुकी है। कॉरपोरेट टैक्स में कटौती इस दिशा में उठाया गया अब तक का सबसे बड़ा फैसला था। वहीं, ''ध्ध् भी लोगों की ्रिंध् का बोझ करने के लिए रेपो रेट में अब तक 1.35 फीसद की कमी कर चुकी है।

इंटेल ने छोटे, मध्यम उपक्रमों के बीच प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिये शुरू की मुहिम

नयी दिल्ली। एजेंसी

प्रौद्योगिकी कंपनी इंटेल ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) मंत्रालय के साथ मिलकर छोटे एवं मध्यम उपक्रमों के बीच प्रौद्योगिकी इस्तेमाल बढ़ाने के लिये एक राष्ट्रव्यापी मुहिम की शुरुआत की है। भारत एसएमई फोरम ने इसकी जानकारी दी है।फोरम के एक सर्वेक्षण के अनुसार, 19 राज्यों के 1,29,537 एमएसएमई में से 34 प्रतिशत से अधिक ने बताया कि वे कर्मचारियों, उपभोक्ताओं तथा आपूर्तिकर्ताओं से संवाद के लिये डिजिटल माध्यमों को अपना रही हैं। हालांकि, इनमें से महज सात प्रतिशत ने ही पूरी तरह से डिजिटल माध्यम को अपनाया है। सर्वेक्षण के अनुसार, प्रौद्योगिकी को अपनाये जाने की निम्न दर का कारण कारोबारी फायदे के बारे में समझ व सलाह का अभाव, प्रौद्योगिकी अपनाने में होने वाले निवेश की लागत का वहन करने में आना-कानी तथा प्रौद्योगिकी का प्रबंधन करने में सक्षम श्रमबल का अभाव है। एमएसएमई मंत्रालय की संयुक्त सचिव अल्का अरोड़ा ने देश के करीब छह करोड़ एमएसएमई के विकास के लिये प्रौद्योगिकी की जरूरत को रेखांकित किया। उन्होंने कहा, ''इनमें से अधिकांश सूक्ष्म श्रेणी में हैं तथा कुछ छोटे एवं मध्यम श्रेणी में हैं लेकिन आज के समय में किसी भी उपक्रम के अगले स्तर पर पहुंचने के लिये प्रौद्योगिकी का महत्व प्रमुख है।''

इंश्योरेंस पॉलिसी के नियमों में हुआ बड़ा बदलाव, अब आपको मिलेंगे ये फायदे

नई दिल्ली। इरडा ने बीमाधारकों को एक बहुत अच्छी सुविधा देने का ऐलान किया है। बीमाधारक अब इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदते समय या उसका रिन्यूअल कराते वक्त अपनी मर्जी का थर्ड पार्टी ऐडमिनिस्ट्रेटर चुन सकते हैं। भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण ने मंगलवार को एक सर्कुलर जारी किया है। इसके मुताबिक इस उप-नियमन के तहत स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर बीमाधारक अपनी पसंद के उस टीपीए को चुन सकता है, जिसके साथ बीमा कंपनी का सर्विस लेवल अग्रीमेंट है।

सर्कुलर के अनुसार, 'स्वास्थ्य बीमा उत्पाद तथा पॉलिसीधारक की भौगोलिक स्थिति के आधार पर बीमा कंपनी टीपीए की संख्या को सीमित कर सकती है और पॉलिसीधारक को इन्हीं में से अपनी पंसद का टीपीए चुनना होगा। बीमा पॉलिसी खरीदते समय या उनका रिन्यूअल कराते वक्त इंश्योरेंस कंपनी ग्राहक को टीपीए की सूची सौंपेगी, जिनमें से वह अपनी पसंद का टीपीए चुन सकता है।

इससे पॉलिसीधारक को क्या फायदा मिलेगा

इस रेग्युलेशंस को इंश्योरेंस रेग्युलेटरी ऐंड डिवेलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (थर्ड पार्टी ऐडमिनिस्ट्रेटर्स- हेल्थ सर्विसेज) (अमेंडमेंट) रेग्युलेशंस, 2019 कहा जा सकता है। इरडा के सर्कुलर के मुताबिक, पॉलिसीधारक बीमा कंपनी द्वारा उपलब्ध कराए गए टीपीए में से अपनी पसंद का टीपीए चुन सकता है. सर्कुलर की प्रमुख बातें:

अगर बीमा कंपनी बीच में किसी टीपीए की सेवा खत्म करती है तो वह अपने पास मौजूद सभी टीपीए की सूची बीमाधारक को उपलब्ध कराएगी, जिनमें से बीमाधारक अपनी पसंद का टीपीए चुनेगा। पॉलिसी बेचते वक्त बीमा कंपनी ग्राहक को अपने पास मौजूद तमाम टीपीए की सूची उपलब्ध कराएगी, जिनमें से वह अपनी पसंद का टीपीए चुनेगा। पॉलिसी के रिन्यूअल के वक्त भी बीमाधारक को अपनी पसंद का टीपीए चुनने का अधिकार होगा।

हालांकि, पॉलिसीधारक को किसी टीपीए की सेवा खत्म कराने या कंपनी को सीधे स्वास्थ्य सेवा मुहैया कराने के लिए आग्रह करने का अधिकार नहीं होगा। अगर किसी पॉलिसीधारक ने किसी टीपीए का चयन नहीं किया है तो बीमा कंपनी बीमाधारक को अपनी पसंद का टीपीए चुनने की मंजूरी दे सकती है। अगर किसी बीमा कंपनी के साथ केवल एक ही टीपीए जुड़ा हुआ है तो पॉलिसीधारक को कोई विकल्प देने की जरूरत नहीं है।

इसरो ने लॉन्च किया पीएसएलवी-सी48, भेजे गए 10 सैटलाइट

हैदराबाद। एजेंसी

भारतीय स्पेस एजेंसी (इसरो) ने श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस स्टेशन से सैटलाइट रिसैट-2बीआर1 लॉन्च कर दिया है। इस सैटलाइट को पीएसएलवी-48 रॉकेट के जरिए बुधवार को लॉन्च किया गया। इस सैटलाइट के साथ नौ और सैटलाइट भेजे गए हैं। बताते चलें कि रिसैट-2बीआर1 एक रेडार इमेजिंग अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटलाइट है। इसका वजन कुल 628 किलोग्राम है। यह प्रक्षेपण इसरो के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह पीएसएलवी की 50वीं उड़ान है। श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपित किया जाने वाला यह 75वां रॉकेट है। यह कृषि, वन और आपदा प्रबंधन में सहायता उपलब्ध कराने के मकसद से तैयार किया गया है। कुल भेजे गए सैटलाइट में इजरायल, इटली, जापान का एक-एक और अमेरिका के छह उपग्रह शामिल है।

इसरो ने बताया है कि इन उपग्रहों का प्रक्षेपण न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के साथ हुए व्यावसायिक करार के तहत किया जा रहा है। स्पेस एजेंसी ने बताया कि रिसैट-2बीआर1 मिशन की उम्र पांच वर्ष है। रिसैट-2बीआर1 से पहले 22 मई को रिसैट-2बी का सफल प्रक्षेपण किया गया था।

इजरायल से है कनेक्शन

रिसैट-2बीआर1 के अलावा पीएसएलवी जिन 9 सैटलाइट को अपने साथ अंतरिक्ष में ले जा रहा है, उनमें से एक इजरायल का है। इसे इजरायल के हर्जलिया साइंस सेंटर और शार हनेगेव हाईस्कूल के स्टूडेंट्स ने मिलकर बनाया है। Duchifat-3 नाम के इस सैटलाइट का वजन महज 2.3 किलो है। यह एक एजुकेशनल सैटलाइट है जिस पर लगा कैमरा अर्थ इमेजिंग के लिए इस्तेमाल किया जाएगा।

जंगलों की सेहत पर रहेगी नजर

इसके अलावा इस पर लगा एक रेडियो ट्रांसपोंडर वायु और जल प्रदूषण पर रिसर्च करने और जंगलों पर नजर रखने के काम आएगा। इसे बनाने वाले तीनों इजरायली स्टूडेंट भी लॉन्च साइट पर होंगे।

विश्व का दूसरा सबसे बड़ा हथियार आयातक है भारत, लेकिन बिक्री में बहुत पीछे: SIPRI

■2018 में पूरे विश्व में करीब 420 अरब डॉलर के हथियारों की बिक्री हुई ■अकेले अमेरिका ने करीब 246 अरब डॉलर का हथियार बेचा ■अमेरिकी कंपनी लॉकहीड मार्टिन ने अकेले 47.3 अरब डॉलर का हथियार बेचा ■भारत की तीन कंपनियों की सामूहिक बिक्री 2018 में 6.9 प्रतिशत घटकर 5.9 अरब अमेरिकी डॉलर

नई दिल्ली। एजेंसी

सिपरी की रिपोर्ट के मुताबिक, 2018 में विश्व की 100 सबसे बड़ी हथियार बनाने वाली कंपनियों ने कुल 420 अरब डॉलर का हथियार बेचा किया। 2017 के मुकाबले इसमें करीब 5 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है। स्टॉकहोम इंटरनैशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट का कहना है कि हथियार बेचने के मामले में अमेरिका अभी भी अव्वल है और उसने कुल उत्पादन का 59 फीसदी, करीब 246 अरब डॉलर का हथियार बेचा है।

भारतीय कंपनियों का योगदान महज 1.4 फीसदी

बात अगर भारत की करें तो सार्वजनिक क्षेत्र की तीन शीर्ष रक्षा कंपनियों की सामूहिक बिक्री 2018 में 6.9 प्रतिशत घटकर 5.9 अरब अमेरिकी डॉलर रह गई। हालांकि इस दौरान वैश्विक स्तर पर हथियारों की बिक्री में बढ़ोतरी हुई है। भारत की रक्षा क्षेत्र की तीनों कंपनियां दुनिया की शीर्ष 100 हथियार आपूर्तिकर्ताओं में आती हैं। हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स 38वें नंबर पर, इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्टरीज 56वें नंबर पर और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स 62वें नंबर पर हैं। तीनों कंपनियों ने मिलकर करीब 1.4 फीसदी हथियारों की बिक्री की है।

सऊदी सबसे ज्यादा हथियार आयात करता है

भारत की हथियार बनाने वाली कंपनियों ने ज्यादातर घरेलू मांगों को पूरा किया है। रिपोर्ट से साफ जाहिर होता है कि भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा हथियार आयातक (सऊदी अरब के बाद) होने के बावजूद डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने में अब तक विफल रहा है। ऐसे में अगर वैश्विक मतभेद की स्थिति में हथियारों की सप्लाई बंद हो जाती है तो भारत के लिए स्थिति चुनौतीपूर्ण हो जाएगी।

लॉकहीड मार्टिन अकेले 11% हथियार बेची

अमेरिकी कंपनी लॉकहीड मार्टिन 2009 से लगातार विश्व में सबसे ज्यादा हथियार बेच रही है। उसने अकेले 47.3 अरब डॉलर (करीब 11%) का हथियार बेचा है। हथियार बेचने के मामले में 8.6 फीसदी हिस्सेदारी के साथ रूस दूसरे, 8.4 फीसदी हिस्सेदारी के साथ इंग्लैंड तीसरे और 5.5 फीसदी हिस्सेदारी के साथ फ्रांस चौथे नंबर पर है। चीन को लेकर पर्याप्त डेटा नहीं होने के कारण उसे लिस्ट में शामिल नहीं किया गया है। हालांकि सिपरी का कहना है कि उसकी भी हिस्सेदारी 3-7 फीसदी तक है।

FASTag 2.0 की तैयारी पार्किंग-पेट्रोल पंप और ई-चालान भरने में करेगा काम

नई दिल्ली। आईपीटी नेटवर्क

फास्टैग को एक दिसंबर से सभी वाहनों के लिए जरूरी कर दिया गया है। फास्टैग के लिए हाइवे पर स्पेशल लेन बनाई गई है। अब इसके दूसरे इस्तेमाल के बारे में भी विचार किया जा रहा है। फास्टैग का इस्तेमाल बहुत जल्द पार्किंग में पेमेंट के लिए किया जाएगा। हैदराबाद एयरपोर्ट पर इसको लेकर पायलट प्रॉजेक्ट का काम शुरू हो चुका है। परिवहन मंत्रालय की तरफ से सोमवार को बयान जारी कर इस बारे में सूचना दी गई है।

1 दिसंबर से फास्टैग हुआ जरूरी

एक दिसंबर के बाद से फास्टैग के बिना ज्यादातर सड़कों पर चलना थोड़ा मुश्किल हो गया है। फास्टैग के लिए हाइवे पर स्पेशल लेन बनाई गई है। उस लेन से बिना फास्टैग वाली गाड़ी गुजरने पर दोगुना टोल वसूला जाएगा। लोगों को जागरूक करने के लिए ऍफ की तरफ से मुहिम चलाई गई और एक दिसंबर तक मुफ्त में फास्टैग बांटे भी गए थे।

फास्टैग 2.0 में सबकुछ डिजिटल होगा

फास्टैग में सुविधा के विस्तार को फास्टैग 2.0 का नाम दिया गया है। सरकार चाहती है कि इसकी मदद से आने वाले दिनों में पार्किंग, पेट्रोल पंप पर पेमेंट, ई-चालान जैसे काम आसानी से किए जा सकें। ऐसा करने से सभी प्रक्रियाएं डिजिटल हो जाएंगी और काम आसान हो जाएगा।

हैदराबाद के बाद दिल्ली एयरपोर्ट की बारी

परिवहन मंत्रालय की तरफ से जारी बयान के अनुसार पायलट परियोजना की शुरूआत दो चरणों में की गई है। पहले चरण में नियंत्रित रूप से पायलट आधार पर परीक्षण किया गया। इसमें केवल आईसीआईसीआई टैग का उपयोग किया जाएगा। दूसरे चरण में फास्टैग का उपयोग हैदराबाद एयरपोर्ट पर पार्किंग मकसद से किया जाएगा। इसमें अन्य बैंकों के टैग को भी रखा जाएगा। जारी बयान के मुताबिक, 'हैदराबाद के बाद परियोजना की शुरूआत दिल्ली एयरपोर्ट पर की जाएगी।

SBI के बाद BoB और यूको बैंक ने भी घटाया लोन पर ब्याज, घटेगी EMI

नई दिल्ली। आईपीटी नेटवर्क

एसबीआई के बाद अब सरकारी क्षेत्र के बैंक ऑफ बड़ौदा और यूको बैंक ने भी मंगलवार को अलग-अलग अवधियों के लिए ब्याज दरों में कटौती कर दी। इससे होम और ऑटो समेत कई लोन सस्ते हो जाएंगे। बैंक ऑफ बड़ौदा ने श्र्ष्ठ में 0.20% तक की कटौती का ऐलान किया। नई दरें 12 दिसंबर से लागू होंगी। यूको बैंक ने MCLR में 0.10% की कटौती करके लोन सस्ता कर दिया है। इसके अलावा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने भी मंगलवार को एक साल की सीमांत लागत आधारित ब्याज दर (एमसीएलआर) को 0.05 प्रतिशत कम करके 8.20 प्रतिशत कर दिया। यूनियन बैंक ने अपनी विभिन्न अवधि के कर्ज पर 0.05 से 0.10 पर्सेंट तक कटौती की है।

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने कहा कि एक साल की अवधि के कर्ज पर एमसीएलआर को 8.25 प्रतिशत से घटाकर 8.20 प्रतिशत किया गया है। इसी तरह, एक दिन के कर्ज पर एमसीएलआर को 0.10 प्रतिशत कम करके 7.75 प्रतिशत किया गया है। एक महीने से छह महीने के अवधि के कर्ज के लिए एमसीएलआर को 7.80 से 8.05 प्रतिशत के बीच रखा है। बैंक ने कहा कि नई दरें 11 दिसंबर से प्रभावी होंगी।

इससे पहले 9 दिसंबर को एसबीआई ने एमसीएलआर आधारित ब्याज दर में 0.10 फीसदी की कटौती का ऐलान किया था। देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक के श्र्ष्ठ में यह कटौती 10 दिसंबर से लागू हो गई। इस चालू वित्त वर्ष में एँ ने लगातार आठवीं बार MCLR में कटौती की है। इस कटौती से SBI एक साल का MCLR अब 8 पर्सेंट से घटकर 7.90 पर्सेंट पर आ गया।

क्या होता है MCLR?

अप्रैल 2016 से लोन पर ब्याज की जगह बैंकों में एमसीएलआर का इस्तेमाल करना शुरू किया गया था। जब आप किसी बैंक से कर्ज लेते हैं तो बैंक द्वारा लिए जाने वाले ब्याज की न्यूनतम दर को आधार दर कहा जाता है। आधार दर से कम दर पर बैंक किसी को लोन नहीं दे सकता। इसी आधार दर की जगह पर बैंक एमसीएलआर का इस्तेमाल करने लगे। इसकी गणना लोन की राशि की सीमांत लागत, आवधिक प्रीमियम, संचालन खर्च और नकदी भंडार अनुपात को बनाए रखने की लागत के आधार पर की जाती है। बाद में इस गणना के आधार पर लोन दिया जाता है। यह आधार दर से सस्ता होता है। इस वजह से होम लोन जैसे लोन्स भी इसके लागू होने के बाद से काफी सस्ते हुए।

कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने बॉन्ड बेचकर जुटाए 8,000 करोड़

मुंबई। एजेंसी

फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (इण्ड) ने खाद्यान्न की भंडारण क्षमता बढ़ाने की योजना को अंजाम देने के लिए बॉन्ड बेचकर 8,000 करोड़ रुपये जुटाए हैं। सरकार की गारंटी वाले इन 10 साल के बॉन्ड पर 7.64% का कूपन रेट ऑफर किया गया है। कंपनी को 247 बिड मिली थीं जिनमें इश्यू साइज के ढाई गुना के बराबर बॉन्ड्स की मांग आई थी। मार्केट के सोर्सेज ने कहा कि रिस्क से परहेज करने की बढ़ती प्रवृत्ति के बीच इन 'जीरो रिस्क' बॉन्ड्स में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, यस बैंक और HDFC बैंक ने पैसा लगाया है। बॉन्ड इश्यू में सब्सक्रिप्शन के बाबत बैंकों से कॉन्टैक्ट नहीं हो पाया है। उन्होंने बताया कि कुछ इंश्योरेंस कंपनियों और बॉन्ड हाउस ने भी एफसीआई के बॉन्ड में पैसा लगाया है।

सेल में शामिल एक बड़े बॉन्ड हाउस के सीनियर एग्जिक्यूटिव ने कहा, 'सरकारी गारंटी के चलते ज्यादा सेफ्टी होने से बॉन्ड की टाइट प्राइसिंग की गई थी।' अगर इण्ड बॉन्ड का कूपन रेट पेमेंट करने में नाकामयाब रहती है तो निवेशकों को पैसा सरकार देगी। यह सेफ्टी फीचर सरकारी गारंटी वाले हरेक बॉन्ड में होता है। ऐसे बॉन्ड का कूपन रेट राज्य सरकार के बॉन्ड्स के मुकाबले लगभग 20-25 बेसिस प्वाइंट यानी 0.20-0.25 पर्सेंटेज प्वाइंट कम होता है। डीलर्स बताते हैं कि राज्य सरकार के बॉन्ड को सॉवरेन सपोर्ट नहीं होने पर उनका कूपन रेट ज्यादा हो सकता है।

इण्ड सरकार की तरफ से अनाज की खरीदारी करती है और यह REC या पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन की तरह बॉन्ड बाजार से बार-बार पैसे नहीं जुटाती है। सोमवार नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डिवेलपमेंट ने भी 7.75% के कूपन रेट वाले 15 साल के बॉन्ड बेचे थे। ईटी ने पांच नवंबर को खबर दी थी कि इण्ड सरकारी गारंटी वाले बॉन्ड्स के जरिए 13,200 करोड़ रुपये जुटाने वाली है। इसका मतलब यह है कि कंपनी के पास और बॉन्ड्स बेचने की गुंजाइश है।

मामले के जानकार सूत्र ने कहा कि इण्ड को खाद्यान्न के रखरखाव के लिए 60,000 करोड़ रुपये से 1.03 लाख करोड़ रुपये तक की जरूरत है। कंपनी ने शॉर्ट टर्म वर्किंग कैपिटल के लिए लेंडर्स के साथ पहले ही करार कर चुकी है। ऐसे में सरकारी गारंटी वाले बॉन्ड से कंपनी को लॉन्ग टर्म फंड मिलेगा। ईटी ने नवंबर के अंतिम हफ्ते में खबर छापी थी कैबिनेट कमेटी ऑन इकनॉमिक अफेयर्स ने FCI की अधिकृत पूंजी को 3,500 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 10,000 करोड़ रुपये करने को मंजूरी दे दी है।

चीन की डिजिटल मुद्रा लाने की योजना

बीजिंग। एजेंसी

चीन ने वैश्विक प्रतिस्पर्धा में आगे रहने के इरादे से खुद की डिजिटल मुद्रा शुरू करने की योजना है। केंद्रीय बैंक ने कुछ शहरों के इसका परीक्षण करने की अनुमति दे दी है। सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार चीन का केंद्रीय बैंक-पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना (पीबीसी) ने डिजिटल करेंसी इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट (डीसीईपी) शुरू करने के लिये कदम उठाया है। चीन ने दुनिया भर में केंद्रीय बैंकों के बीच वैश्विक प्रतिस्पर्धा में आगे रहने तथा वित्तीय संप्रभुता संरक्षित रखने में मदद को लेकर यह पहल की है। बैंक शेनझेन और गुआंगदोंग प्रांत शहरों में डिजिटल मुद्रा का परीक्षण करने की तैयारी में है। अगले साल परीक्षण का दायरा बढ़ाया जा सकता है।

दत्तात्रेय जयंती (11 दिसंबर) पर विशेष

त्रिदेव के अंश हैं भगवान दत्तात्रेय

भारत में दत्तात्रेय एक ऐसे अवतार हैं, जिन्होंने 24 गुरुओं से शिक्षा ली। इनका पृथ्वी पर अवतार मार्गशीर्ष की पूर्णिमा को प्रदोष काल में हुआ था, जो इस बार 11 दिसंबर को है। इनकी गणना भगवान विष्णु के 24 अवतारों में छठे स्थान पर की जाती है। मान्यता है कि ये स्मरण करने मात्र से ही अपने भक्तों के पास पहुंच जाते हैं। इसीलिए इन्हें 'स्मृतिमात्रानुगन्ता' या 'स्मर्तृगामी' भी कहा गया है। आदि शंकराचार्य ने भगवान दत्तात्रेय की स्तुति में लिखा है- '*आदौ ब्रह्मा मध्ये विष्णुरन्ते देवः सदाशिवः*
मूर्तित्रयस्वरूपाय दत्तात्रेयाय नमोस्तु ते॥
ब्रह्मज्ञानमयी मुद्रा वस्त्रे चाकाशभूतले
प्रज्ञानघनबोधाय दत्तात्रेयाय नमोस्तु ते॥'

जो आदि में ब्रह्मा, मध्य में विष्णु तथा अन्त में सदाशिव है, उन भगवान दत्तात्रेय को बार-बार नमस्कार है। ब्रह्मज्ञान जिनकी मुद्रा है, आकाश और भूतल जिनके वस्त्र हैं तथा जो साकार प्रज्ञानघन स्वरूप है, उन भगवान दत्तात्रेय को बार-बार नमस्कार है।

श्रीमद्भागवत पुराण के अनुसार, एक बार महर्षि अत्रि ने भगवान विष्णु को पुत्र के रूप में पाने की इच्छा की। भगवान विष्णु ने महर्षि अत्रि की इच्छा को सम्मान देते हुए स्वयं को उन्हें दे दिया। भगवान दत्तात्रेय के नाम में इस भाव को देखा जा सकता है। यह दत्त और आत्रेय के संयोग से बना है। 'दत्त' यानी दिया हुआ और आत्रेय यानी अत्रि का पुत्र। इनकी माता देवी अनुसूइया थीं।

गुजरात का गिरनाथ क्षेत्र श्री दत्तात्रेय का सिद्धपीठ है। इसके अलावा इनके मुख्य तीर्थों में वाराणसी, पंढरपुर, प्रयागराज, उडुपी, श्रीनगर, आबू पर्वत आते हैं। इन्हें त्रिदेव- ब्रह्मा, विष्णु और महेश का अंश माना जाता है। इसीलिए इनके तीन सिर और छह भुजाएं हैं। इनके साथ हमेशा पृथ्वी रूप में गाय और वेद के रूप में चार श्वान रहते हैं। दत्तात्रेय तीनों ईश्वरीय शक्तियों से संपन्न थे।

श्रीमद्भागवत में दत्तात्रेय जी ने कहा है- अपनी बुद्धि के अनुसार मैंने बहुत से गुरुओं का आश्रय लिया। इनके 24 गुरु किसी न किसी रूप में प्रकृति और मनुष्यता के संदेश का संकेत करते हैं। इनके 24 गुरुओं में- पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, समुद्र, चंद्रमा व सूर्य जैसे आठ प्रकृति तत्व हैं। वहीं झींगुर, सर्प, मकड़ी, पतंग, भौंरा, मधुमक्खी, मछली, कौआ, कबूतर, हिरण, अजगर व हाथी सहित 12 जंतु शामिल हैं। इनके चार मानवीय गुरुओं में बालक, लोहार, कन्या और पिंगला नामक वेश्या भी शामिल हैं।

दत्तात्रेय ने मानवता को यह संदेश दिया है कि हमें जिससे भी किसी न किसी रूप में कोई भी शिक्षा मिली, वे हमारे गुरु हुए। दूसरे शब्दों में कहें, तो हर किसी से कुछ न कुछ सीखा जा सकता है।

स्वप्निल डागुर

धर्म है मनुष्य की शाश्वत चाह

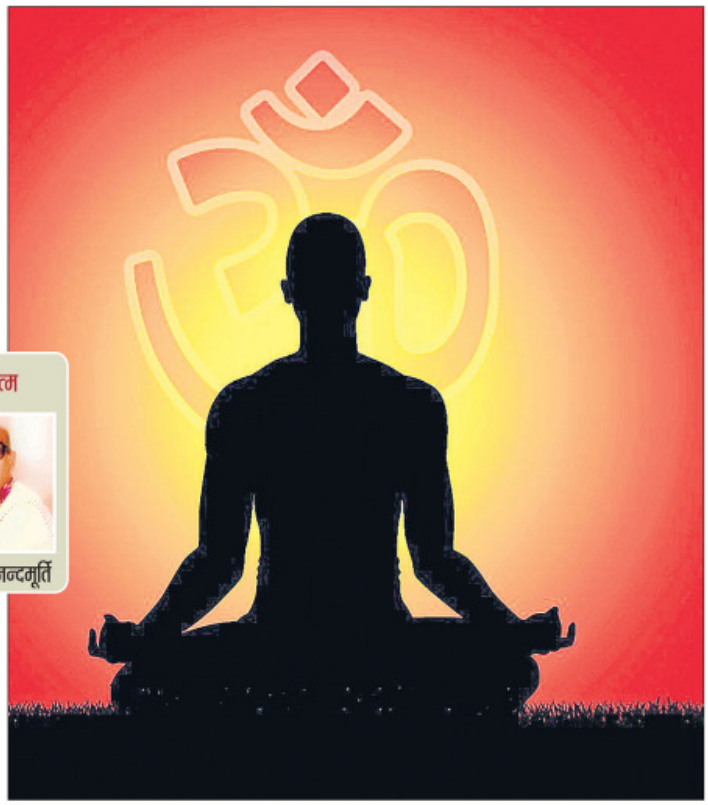

मनुष्य ने जब यह अनुभव किया कि अपने जीवन में वह जो भी सुख-दुख, आनन्द की अनुभूति करता है, वह सिर्फ देह के कारण नहीं है, इसके पीछे कोई प्रेरक शक्ति है। इससे उसके मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई और उसने समझा कि एक परम सत्ता है, जो उसे चला रही है।

अध्यात्म

श्री श्री आनन्दमूर्ति

मनुष्य प्राण से अलग होना क्यों नही चाहता? हर जीव, जीवित रहना क्यों चाहता है? इसका कारण यही है कि शरीर जब तक क्रियाशील है, शरीर में जब तक प्राण है, तब तक मन सुख-भोग कर सकता है। दरअसल शरीर सुख-भोग नहीं करता है, सुख-भोग करता है मन। जिस दशा में रहने से मनुष्य के मन में चंचलता बढ़ जाती है, वह उस दशा में सुख-भोग नहीं कर सकता।

स्थिर बैठकर खाना खाते समय जो स्वाद मिलता है, दौड़ते वक्त खाना खाने में वह स्वाद नहीं मिल सकता। मनुष्य चाहता है कि उसका मन सुख-भोग करे। मन सुख-भोग तभी तक कर सकता है, जब तक मनुष्य में प्राण है। यदि प्राण नहीं है, तो मन का सुख-भोग भी नहीं होता है। इसीलिए मनुष्य प्राण से अलग होना नहीं चाहते। जीवन प्यारा क्यों है, इसकी सिर्फ यही वजह है।

मनुष्य का सुख और पेड़-पौधों तथा पशुओं का सुख सोलहों आने एक नहीं है। कारण इसका यही है कि मनुष्य का मन सिर्फ देह केंद्रित नहीं है। मनुष्य का मन देहातीत भी है, किन्तु वह शरीर के एक विशेष बिंदु में, खोपड़ी की एक विशेष जगह में क्रियाशील है। तो यह है मनुष्य का आदिम प्रश्न। जब मनुष्य बहुत कुछ पाता है, जितना वह चाहता था, उससे अधिक पाता है, तो चिल्लाता है और चिल्लाकर अपने सुख को व्यक्त करता है। जब मनुष्य अपनी चाह या मांग के अनुसार भी नहीं पाता है, तब वह रो-रोकर अपनी अनुभूति को व्यक्त करता है।

अर्थात किसकी प्रेरणा से हम बात करते हैं? इसके पीछे क्या है? सुख बोध के कारण अथवा सुख बोध के अभाव के कारण मनुष्य बात करते हैं? भाषा के द्वारा मनुष्य खुद को व्यक्त करते हैं। तो इसके पीछे प्रेरणा देने वाली शक्ति कौन है? जो आनन्दस्वरूप है, आनन्द जिनका घर है, जो खुद आनन्दमय हैं, उन्हीं से यह प्रेरणा आती है। तब मनुष्य ने समझ लिया कि यह जो व्यक्त करने की अभिलाषा है, यह जो भोगात्मक, सुखात्मक जगत है तथा आनन्दात्मक भाव को देखने, सुनने की अभिलाषा है उसके पीछे एक शक्ति है। वह शक्ति हैं परमपुरुष।

मनुष्य ने समझ लिया कि और एक सत्ता है, जिनकी प्रेरणा से ये सब घटनाएं हो रही हैं। उस सत्ता से पेड़-पौधे परिचित नहीं हैं। परिचित होने के लिए मानसिक तथा अतिमानसिक शक्ति उनमें नहीं है। जीव-जन्तुओं में भी नहीं है। किन्तु परमपिता की कृपा से मनुष्य में वह शक्ति निहित अवस्था में है। उसी रोज से उसी सुप्रभात से मनुष्य के जीवन में, मनुष्य के जगत में धर्म का शुभागमन हुआ। तो मनुष्य की यह जो प्रथम जिज्ञासा थी, इस जिज्ञासा के उत्तर की खोज में आज तक मनुष्य ने जो कुछ भी किया है, वही है धर्म साधना का गुप्त मंत्र। मनुष्य ने समझ लिया कि यह विश्व ब्रह्माण्ड जिस चेतना से स्पन्दित है, इस ब्रह्माण्ड में जिनके कारण आनन्दात्मक अनुभूति हो रही है, वे ही मेरे, वे ही हमारे लक्ष्य हैं। वे ही हमारी परागति हैं। उनके सिवाय हमारे सामने और कोई दूसरा लक्ष्य नहीं रह सकता।

आज के मनुष्य में भी वही प्रथम जिज्ञासा है; मगर उस प्रथम जिज्ञासा का उत्तर भी आज के मनुष्य के पास पहुंच गया है। प्राचीन काल के मनुष्य को इस उत्तर को खोजने में जितनी मेहनत करनी पड़ी, उतनी आज के मनुष्य को नहीं करनी है। आज के मनुष्य को सिर्फ चलना है, सिर्फ आगे बढ़ना है और अवश्य ही वे लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। आज उन्हें किस तरह से आगे बढ़ना है, सिर्फ यही सीखना है। आज के मनुष्य को यह भी वरदान मिल गया कि तुम आगे बढ़ते रहो, परमपुरुष तुम्हारे साथ हैं। जो तुम्हें पाना है, वो तुम पा जाओगे। उसका संकेत तुमको मिल चुका है। तुम चलते रहो। तुम्हें गिरने का भी डर नहीं है, क्योंकि परम पुरुष तुम्हारे साथ है।

प्रस्तुतिः दिव्यचेतनानन्द अवधूत

आस्था स्थली: नीलकंठ महादेव मंदिर, कुंभलगढ़, राजस्थान

देश के सबसे बड़े शिवलिंगों में से एक

राजस्थान के कुंभलगढ़ किले में कई ऐतिहासिक मंदिर हैं, जिनमें महादेव शिव का भी एक बहुत सुंदर मंदिर शामिल है। यह मंदिर अपने विशाल शिवलिंगम और नक्काशीदार बरामदे के लिए जाना जाता है। मंदिर का निर्माण पंद्रहवीं सदी में कुंभलगढ़ किले के निर्माण के साथ ही हुआ था। सन 1457 में महाराणा कुंभा ने इस मंदिर का निर्माण कराया था।

हनुमान पोल से अंदर प्रवेश करने के बाद दाहिनी तरफ नीलकंठ महादेव का सुंदर मंदिर है। इस मंदिर में काले पत्थर का विशाल शिवलिंगम स्थापित है। मंदिर में स्थापित इस शिवलिंगम को देश के विशालतम लिंगम में गिना जाता है। नीलकंठ मंदिर के शिवलिंगम की ऊंचाई छह फीट है। मंदिर के गर्भगृह की कलात्मकता भी अद्भुत है।

नीलकंठ महादेव महाराणा कुंभा के आराध्य देव थे। वे नियमित इस मंदिर में पूजा किया करते थे। यह राजस्थान के अत्यंत सुंदर शिवमंदिरों में से एक है।

नीलकंठ महादेव का यह मंदिर अपने ऊंचे-ऊंचे सुन्दर स्तम्भों वाले बरामदे के लिए भी जाना जाता है। इस तरह के बरामदे वाले मंदिर प्रायः बहुत कम देखने को मिलते हैं। इस मंदिर के भवन में कुल 36 कलात्मक स्तंभों का निर्माण कराया गया है। मंदिर की संरचना दो मंजिलों वाली है। कहा जाता है कि महाराणा कुंभा स्वयं वास्तुशास्त्र के बड़े जानकार थे। उनका वास्तुज्ञान इस मंदिर के निर्माण में खूब झलकता है। मंदिर की इस स्थापत्य शैली को कर्नल टॉड जैसे भारतविद इतिहासकार ग्रीक (यूनानी) शैली बतलाते हैं। हालांकि कई विद्वान उनके इस तर्क से सहमत नहीं हैं।

नीलकंठ मंदिर में आज भी नियमित रूप से पूजा-अर्चना होती है। आम श्रद्धालु यहां सुबह से शाम यानी सूर्योदय से सूर्यास्त तक नीलकंठ के दर्शन कर सकते हैं। कुंभलगढ़ किले में आने वाले सैलानी अकसर इस मंदिर के भी दर्शन जरूर करते हैं।

कैसे पहुंचें: कुंभलगढ़ किले, जिसमें यह मंदिर स्थित है, की दूरी राजस्थान के उदयपुर शहर से करीब 60 किलोमीटर है। उदयपुर से टैक्सी या फिर बस द्वारा यहां पहुंचा जा सकता है। उदयपुर देश के विभिन्न शहरों से रेल, सड़क और वायु मार्ग से जुड़ा हुआ है।

माधवी रंजना

वियतनाम से कंपोनेंट इंपोर्ट बढ़ा, हैंडसेट मेकर्स में ड्यूटी बढ़ने का डर

वियतनाम से मोबाइल फोन के कंपोनेंट्स का इंपोर्ट मौजूदा वित्त वर्ष की पहली छमाही में 1 अरब डॉलर से ज्यादा हो गया है जो साल भर पहले 80 करोड़ डॉलर था

नई दिल्ली। एजेंसी

वियतनाम से मौजूदा वित्त वर्ष की पहली छमाही में मोबाइल फोन के 1 अरब डॉलर से ज्यादा के कंपोनेंट्स के इंपोर्ट ने डोमेस्टिक हैंडसेट मेकर्स के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। हैंडसेट मेकर्स ने इसको देखते हुए सरकार से मोबाइल फोन कंपोनेंट्स के इंपोर्ट पर एडिशनल ड्यूटी नहीं लगाने का अनुरोध किया है। उन्होंने सरकार से फेज्ड मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्राम (PMP) के तहत मौजूदा आयात शुल्क पर दोबारा विचार करने की अपील की है। सरकार की योजना इस प्रोग्राम के जरिए आयात में कमी लाने और स्थानीय उत्पादन को बढ़ावा देने की है।

वियतनाम से मोबाइल फोन के कंपोनेंट्स का इंपोर्ट मौजूदा वित्त वर्ष की पहली छमाही में 1 अरब डॉलर से ज्यादा हो गया है जो साल भर पहले 80 करोड़ डॉलर था। इंडिया में हैंडसेट बनानेवाली कंपनियों के प्रतिनिधि उद्योग संगठन ने कहा कि था यह उससे पिछले साल 60 करोड़ डॉलर का था। हैंडसेट मेकर्स का कहना है कि उन स्थितियों में इंपोर्ट ड्यूटी लगाना बेमानी है जिसमें सभी आसियान देशों-खासतौर पर वियतनाम, कोरिया और जापान से उन प्रॉडक्ट्स के मंगाने पर जीरो इंपोर्ट ड्यूटी लगती है जिसका फायदा बहुत सी कंपनियां पहले से उठा रही हैं।

हैंडसेट मेकर्स एसोसिएशन की तरफ से मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ष्ठ्ठ को भेजे गए लेटर के मुताबिक, 'इंपोर्ट डेटा हैरतंगेज तरीके से काफी ज्यादा हैं। ऐसे में इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने पर हम उसका बोझ उठाने की स्थिति में नहीं होंगे। असल में सरकार को इस बारे में विचार करना चाहिए कि क्या इंपोर्ट पर लगी कुछ ड्यूटी को जारी रहने दिया जाना चाहिए? इंपोर्ट पर एडिशनल ड्यूटी नहीं होनी चाहिए, साथ ही बेसिक कस्टम्स ड्यूटी के बाकी कंपोनेंट को वापस ले लिया जाना चाहिए। वियतनाम के इंपोर्ट को स्टडी करके सब असेंबली और कंपोनेंट्स के इंपोर्ट पर सभी मौजूदा इश्इ ड्यूटी पर गंभीरता से विचार किए जाने की जरूरत है।'

इलेक्ट्रॉनिक प्रॉडक्ट्स के इंपोर्ट पर लगाम लगाने के लिए हैंडसेट मेकर्स ने ड्यूटी लगाने का सुझाव दिया था। उन्होंने सरकार से कहा था कि इसकी शुरुआत मोबाइल फोन से करके कंपोनेंट तक लाई जा सकती है। उन्होंने वॉल्यूम जेनरेट करने और एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा देने के मकसद से तीन साल पहले यह सलाह दी थी। इस पर सरकार ने आधा दर्जन से ज्यादा मोबाइल फोन कंपोनेंट्स के 15% तक की बेसिक कस्टम्स ड्यूटी लगा दी थी जबकि पूरी तरह निर्मित मोबाइल फोंस पर 20% की इंपोर्ट ड्यूटी थी। भारत पूरी तरह से निर्मित मोबाइल फोन का मैन्युफैक्चरर और एक्सपोर्टर बना गया है, लेकिन यहां कंपोनेंट मेकर्स का इकोसिस्टम नहीं बन पाया है। गौरतलब है कि एपल, सैमसंग, शाओमी इंडिया में 4जी डिवाइस बनाती हैं और उनका निर्यात करती हैं। एसोसिएशन के मुताबिक, 'इंपोर्ट सब्स्टिटयूशन कॉन्सेप्ट अपना काम कर चुका है।' नेशनल पॉलिसी ऑन इलेक्ट्रॉनिक्स 2019 में 190 अरब डॉलर की मैन्युफैक्चरिंग और 110 अरब डॉलर के एक्सपोर्ट का टारगेट दिया गया है। इसके जरिए इंडिया को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने पर फोकस किया गया है, जो समय के साथ सब असेंबली और कंपोनेंट इंडस्ट्री को अपनी तरफ खींचेगा।

वाहन निर्माताओं से की जैव-ईंधन आधारित वाहन बनाने की अपील

नयी दिल्ली। एजेंसी

केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री ने शुक्रवार को वाहन निर्माता कंपनियों से कहा कि वे पर्यावरण के अनुकूल ऐसे वाहन बनायें जिसमें जैव ईंधनों का इस्तेमाल हो सके। उन्होंने कहा कि अभी देश जिन प्रमुख चुनौतियों से जूझ रहा है, वायु प्रदूषण उनमें से एक है। अतः वाहन निर्माता कंपनियों को वैकल्पिक ईंधन वाले वाहनों पर ध्यान देना चाहिये ताकि देश में हरित और सुरक्षित आवागमन पारिस्थितिकी सुनिश्चित हो सके। गडकरी ने टोयोटा के इलेक्ट्रिक वाहन प्रौद्योगिकी: प्रदर्शन एवं प्रायोगिक संचालन (हाइब्रिड, इलेक्ट्रिक एवं हाइड्रोजन वाहन) में कहा कि इससे न सिर्फ पर्यावरण में प्रदूषण कम होगा बल्कि इससे किसानों की आय बढ़ाने में भी मदद मिलेगी। उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक तरीके से टोल जमा किये जाने के बारे में कहा कि राष्ट्रीय राजमार्गों पर स्थित टोल प्लाजाओं पर पहले ही 50 प्रतिशत से अधिक लेन-देन फास्टैग के जरिये हो रहा है। उन्होंने फास्टैग अपनाने की अपील करते हुए कहा कि इससे टोल प्लाजाओं पर वाहनों का आवागमन सरल एवं तेज होगा। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा 15 दिसंबर तक निःशुल्क फास्टैग दिये जाने की घोषणा को भी दोहराया।

जल्द ही अर्द्धसैनिक बल पहनेंगे खादी की वर्दी

नयी दिल्ली। आईपीटी नेटवर्क

खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) ने सोमवार को कहा कि देश में अर्द्धसैनिक बल जल्द ही खादी की वर्दी पहनेंगे। इस संदर्भ में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अर्द्धसैनिक बलों के महानिदेशकों को निर्देश दिया है। केवीआईसी ने एक बयान में कहा, "इससे खादी एवं ग्रामोद्योग उत्पादों को बढ़ावा मिलेगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में सभी अर्द्धसैनिक बलों के महानिदेशकों को वर्दी में खादी कपड़े का उपयोग करने को कहा है। साथ ही अचार, पापड़, शहद, साबुन, शैंपू, चाय, सरसों तेल जैसे गांवों के उद्योग से बने सामान का उपयोग भी करने को कहा।" केवीआईसी के चेयरमैन वी के सक्सेना ने कहा कि अर्द्धसैनिक बलों के लिये सूती और जाड़े के मौसम के हिसाब से वर्दी, कंबल आदि जैसे उत्पादों के नमूने तैयार किये गये हैं। उसे अंतिम मंजूरी के लिये कुछ बलों को भेजे गये हैं।"उन्होंने कहा, "इस कदम से न केवल खादी एवं ग्रामोद्योग का कारोबार दोगुना होगा बल्कि खादी दस्तकारों के लिये और रोजगार के अवसर सृजित होंगे...।" फिलहाल खादी एवं ग्रामोद्योग का कारोबार करीब 75,000 करोड़ रुपये है।

विदेशीमुद्रा भंडार 451 अरब डॉलर के ऊपर

मुंबई। आईपीटी नेटवर्क

देश का विदेशीमुद्रा भंडार 29 नवंबर को समाप्त सप्ताह में 2.484 अरब डॉलर की वृद्धि के साथ 451.08 अरब डॉलर की नई ऊंचाई को छू गया । भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा शुक्रवार को जारी साप्ताहिक आंकड़ों में यह जानकारी दी गई है। इससे पिछले सप्ताह देश का विदेशीमुद्रा भंडार 34.7 करोड़ डॉलर बढ़कर 448.6 अरब डॉलर पर था। बृहस्पतिवार को पांचवें द्वैमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए रिजर्व बैंक के गवर्नर शशिकांत दास ने कहा कि अप्रैल के बाद से विदेशीमुद्रा भंडार 38.8 अरब डॉलर बढ़कर तीन दिसंबर को 451.7 अरब डॉलर की ऊंचाई को छू गया। समीक्षाधीन सप्ताह में विदेशी मुद्रा आस्तियां 26.42 करोड़ डॉलर बढ़कर 419.367 अरब डॉलर हो गयीं।इस दौरान स्वर्ण आरक्षित भंडार 14.8 करोड़ डॉलर घटकर 26.648 अरब डॉलर रहा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) के पास देश का विशेष आहरण अधिकार भी, सप्ताह के दौरान 40 लाख डॉलर घटकर 1.436 अरब डॉलर रहा। आंकड़ों के मुताबिक, मुद्राकोष के पास देश के आरक्षित भंडार की स्थिति भी 60 लाख डॉलर घटकर 3.629 अरब डॉलर रह गई।

जेवर हवाईअड्डा बनाने का काम 'ज्यूरिख एयरपोर्ट इंटरनेशनल' को सौंपने को मंजूरी

लखनऊ। एजेंसी

उत्तर प्रदेश मंत्रिमण्डल ने जेवर हवाईअड्डे के निर्माण का जिम्मा 'ज्यूरिख एयरपोर्ट इंटरनेशनल' को सौंपने के निर्णय पर सोमवार को मुहर लगा दी। प्रदेश सरकार के प्रवक्ता कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह ने मंत्रिमण्डल की बैठक के बाद संवाददाताओं को बताया कि जेवर में बनने वाले 'नोएडा इंटरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट' के निर्माण के लिये प्राप्त निविदा में सबसे उपयुक्त पेशकश रखने वाली कम्पनी ज्यूरिख एयरपोर्ट इंटरनेशनल को चुना गया। राज्य मंत्रिमंडल ने आज इस फैसले पर मुहर लगा दी है। उन्होंने बताया कि हवाईअड्डे के लिये चार निविदाएं आयी थीं। उसके औसत भारांक के आधार पर ज्यूरिख एयरपोर्ट इंटरनेशनल को चुना गया है। कंपनी ने सरकार को प्रति यात्री 400.97 रुपये देने का प्रस्ताव रखा है जो सबसे ज्यादा है। सिंह ने बताया कि हमारा अनुमान है कि जेवर एयरपोर्ट का निर्माण कार्य अगले साल फरवरी तक शुरू हो जाएगा। उन्होंने कहा कि यह देश में अपनी तरह की पहली परियोजना है जिसमें शुरुआती निविदा बोली के दौरान किये गये संशोधनों के बाद तकनीकी दक्षता या वित्तीय निविदा प्रक्रिया में एक भी संशोधन की जरूरत नहीं पड़ी। नीति आयोग समेत हर जगह इसकी प्रशंसा हो रही है कि उत्तर प्रदेश ने जो आदर्श बनाये हैं, उन्हें निविदा की रूलबुक के तौर पर सहेजा जाए। बाद में प्रदेश के नागर उड्डयन मंत्री नंद गोपाल गुप्ता ने 'भाषा' को बताया कि आज का दिन उत्तर प्रदेश के विकास के इतिहास का यादगार दिन है। उन्होंने कहा कि जेवर न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे देश के लिये जरूरी है। इसके लिये जरूरी निविदा प्रक्रिया में कोई भी विलम्ब नहीं हुआ। इसने पूरे देश के सामने उदाहरण पेश किया है। मालूम हो कि 5,000 हेक्टेयर से भी ज्यादा क्षेत्र में बनने जा रहे जेवर हवाई अड्डे की अनुमानित निर्माण लागत लगभग 30,000 करोड़ रुपए है। इसके निर्माण के लिए चार कंपनियों एनकोरेज इन्फ्राट्रक्चर इन्वेस्टमेंट होल्डिंग्स लिमिटेड, अडाणी इंटरप्राइजेज लिमिटेड, डायल और ज्यूरिख एयरपोर्ट इंटरनेशनल ने निविदा पेश की थी।

इकॉनमी में तेजी से बढ़ रहा करंसी सर्कुलेशन, 21 लाख करोड़ के नोट चलन में

नई दिल्ली। आईपीटी नेटवर्क

करीब तीन साल पहले 8 नवंबर 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्लैकमनी के खिलाफ नोटबंदी का फैसला लिया था और 500 और 1000 रुपये के नोट बैन कर दिए गए थे। नोटबंदी के बाद डिजिटल इकॉनमी को मजबूत करने के लिए कई पहल की गई। नतीजा यह रहा कि 2016-17 में इकॉनमी में करंसी सर्कुलेशन घटकर 13 लाख करोड़ पर पहुंच गया था, लेकिन तीन सालों के भीतर मार्च 2019 तक करंसी सर्कुलेशन एकबार फिर से 21 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया है। वित्त राज्यमंत्री अनुराग ठाकुर ने लोकसभा में लिखित में यह जवाब दिया।

सदन को दी गई जानकारी के मुताबिक नोटबंदी के बाद मार्च 2017 में करंसी सर्कुलेशन 13 लाख करोड़ था, मार्च 2018 में यह आंकड़ा पहुंच कर 18 लाख करोड़ हो गया और मार्च 2019 में तो यह 21 लाख करोड़ को पार कर गया। नोटबंदी से ठीक पहले मार्च 2016 में इकॉनमी में करंसी सर्कुलेशन करीब 16.41 लाख करोड़ था।

सुधर रही गरीबों की दशा, पर अमीर ज्यादा तेजी से हो रहे और अमीर

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी के समय कहा था उन्होंने नोटबंदी का फैसला आतंकवाद को फंडिंग रोकने, भ्रष्टाचार कम करने और ब्लैकमनी पर लगाम करने के लिए किया था। लेकिन कुछ दिनों बाद ही 2000 के नोट को लॉन्च किया गया और 500 के नए नोट को भी नए रूप में पेश किया गया।

नई जीएसटी रिटर्न प्रणाली को लेकर लोगों की राय जानने के लिये पहल

नयी दिल्ली। एजेंसी

केन्द्रीय जीएसटी और राज्य जीएसटी से जुड़े प्राधिकरण शनिवार को नए जीएसटी रिटर्न के लिए राष्ट्रव्यापी जीएसटी हितधारक प्रतिक्रया दिवस मनाएंगे। इसका मकसद नए जीएसटी रिटर्न के बारे में मौके पर ही आवश्यक प्रतिक्रियाएं प्राप्त करना है।नई प्रणाली एक अप्रैल 2020 से अमल में आएगी।आधिकारिक बयान के तहत इसके तहत अनुपालन में हो रही आसानी के आकलन और इन नये रिटर्नों की अपलोडिंग पर जोर दिया जाएगा ताकि जब ये रिटर्न भरना अनिवार्य हो जाएं, तो कारोबारियों को किसी भी तरह की कठिनाइयों का सामना न करना पड़े। इस प्रतिक्रिया (फीडबैक) से जुड़े इन सत्रों में उद्योग मंडल, करदाताओं, कर विशेषज्ञ एवं अनुपालन प्रबंधकों का प्रतिनिधित्व करने वाले अन्य संगठन भाग लेंगे। इस अवसर पर कर अधिकारी भी उपस्थित रहेंगे, जो करदाताओं का मार्गदर्शन करेंगे और इसके साथ ही नए रिटर्नों को उपयोग में लाने के लिए उनकी सहायता करेंगे। जीएसटी (वस्तु एवं सेवा कर) को लागू करने के बाद पहली बार ऐसा हो रहा है कि इतने बड़े पैमाने पर करदाता परामर्श की व्यवस्था की गई है।

www.eng-expo.co.in
www.eng-expo.in

Why Should You
Participate in Madhya Pradesh ?

- Explore the unexplored opportunities.
- Biggest automobile hub in India.
- Most flourishing food and grain industry.
- Industrial Development on a rapid pace in Plastic Parks, Textile Parks, SEZs, Pharma Zones.
- Both IIMs and IITs are here
- Cleanest city of India third time in a row (IT'S A HATTRICK).
- Fast infrastructure development.
- Centrally connected transport system.
- Good, peaceful and conducive atmosphere for business development.
- Well equipped communication network.
- Proactive initiatives by the state government.

Central India's Largest SME Exhibition

Industrial ENGINEERING EXPO

CONCURRENT EVENTS

3rd International Industry & Technology Expo

PLAST PACK & PRINT EXPO 2019

ELECTRICALS & ELECTRONICS EXPO 2019

INDORE 20 21 22 23 DEC 2019

LABHGANGA EXHIBITION CENTRE

SPONSORED BY

CO-SPONSORED BY

ORGANISED BY

CONCURRENT EVENT ORGANISED BY

SPONSORED BY

SUPPORTED BY

For Participation Call

9826887800, 9826497000, 9981224262, 9827044408

futuretradefairs@gmail.com, industrialenggexpo@gmail.com

स्वामी/मुद्रक/प्रकाशक सचिन बंसल द्वारा अपनी दुनिया प्रिंटर्स, 13, प्रेस काम्पलेक्स, ए.बी. रोड, इंदौर से मुद्रित एवं 18, सेक्टर-डी-2, सांवेर रोड, इंडस्ट्रीयल एरिया, जिला इंदौर (म.प्र.) से प्रकाशित। संपादक- सचिन बंसल

सूचना/चेतावनी- इंडियन प्लास्ट टाइम्स अखबार के पूरे या किसी भी भाग का उपयोग, पुन: प्रकाशन, या व्यावसायिक उपयोग बिना संपादक की अनुमति के करना वर्जित है। अखबार में छपे लेख या विज्ञापन का उद्देश्य सूचना और प्रस्तुतिकरण मात्र है। अखबार किसी भी प्रकार के लेख या विज्ञापन से किसी भी संस्थान की सिफारिश या समर्थन नहीं करता है। पाठक किसी भी व्यावसायिक गतिविधि के लिए स्वविवेक से निर्णय करें। किसी भी विवाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र इंदौर, मप्र रहेगा।